विचार बिन्दु

जो वस्तु आनंद प्रदान नहीं कर सकती, वह सुन्दर हो ही नहीं सकती। –प्रेमचंद

कच्ची नींव पर अच्छी इमारत नहीं बन सकती

राष्ट्रीय स्तर की संस्था 'प्रथम' द्वारा ग्रामीण भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को नापने के लिए सर्वेक्षण 2005 से किया जा रहा है। सर्वेक्षण के आधार पर प्रति वर्ष एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो ASER (Annual Status of Education Report) के नाम से जानी जाती है। 2014 तक यह प्रति वर्ष जारी होती थी किन्तु इसके बाद यह हर दो साल में जारी की जा रही है। पहले केवल 5 से 14 वर्ष के बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन किया जाता था। 2017 में पहली बार 14 से 18 वर्ष के बच्चों-युवाओं के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह सर्वे किया गया।

वर्ष 2023 की रिपोर्ट 'बियोंड बेसिक' के नाम से जारी की गई। इस रिपोर्ट में 14 से 18 वर्ष के किशोरों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। यह सर्वेक्षण भारत के 26 राज्यों के 28 जिलों में किया गया। राजस्थान में इस सर्वेक्षण हेतु भीलवाड़ा जिले का चयन किया गया।

इस रिपोर्ट के आधार पर जो परिणाम सामने आए हैं वे चिंता जनक हैं।

पहले इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षो का उल्लेख करना उचित होगा।

14 से 18 वर्ष के किशोरों में 86.8 प्रतिशत किसी न किसी शिक्षण संस्था में नामांकित हैं। 14 वर्ष से कम आयु के 3.9% नामांकित नहीं हैं जबकि 18 वर्ष से कम आयु के 39% नामांकित नहीं हैं। अध्ययनरत में से अधिकांश नामांकित युवा कला संकाय में नामांकित हैं। 11वीं कक्षा या उसके ऊपर की कक्षा में अध्ययन करने वाले किशोर में से 55.7% कला संकाय में 31.7% किसी तकनीकी या विज्ञान संकाय में एवं 9.4% वाणिज्य संकाय में नामांकित हैं।

सर्वेक्षित युवाओं में मातृभाषा में पढ़ने-लिखने और गणना की मूल दक्षताओं का आकलन किया गया। यह भी देखा गया कि वह इन योग्यताओं को किस प्रकार अपने दिन प्रतिदिन के काम आने वाली गतिविधियों में उपयोग कर सकते हैं।

14 से 18 वर्ष के 25% युवा, कक्षा 2 की मातृभाषा में लिखी हुई किसी पुस्तक को बिना अटके हुए नहीं पढ़ सकते थे।

सर्वेक्षित युवाओं में लगभग 50%, तीन अंको की संख्या में एक अंक की संख्या का भाग देने में परेशानी महसूस कर रहे थे, जबकि यह दक्षता साधारणतया कक्षा तीन और चार के स्तर पर प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

बालिकाओं में 76% पढ़ने में समर्थ थी जो की बालकों की तुलना में बेहतर है क्योंकि लड़कों में 70..9% ही पढ़ने में समर्थ थे।

85% सर्वेक्षित युवा, स्केल के माध्यम से लंबाई नाप सकते हैं यदि उसे जीरो सेंटीमीटर से प्रारंभ किया जाए। जैसे ही इसे किसी अन्य स्थान से प्रारंभ किया जाए तो यह संख्या घटकर केवल 39%रह जाती है। 50% के लगभग युवा ही समय और भार से संबंधित गणना के सरल प्रश्न हल कर सकते में समर्थ थे। गणना के सभी कार्य लड़कियों की अपेक्षा लड़के बेहतर कर पाते थे।

लगभग एक तिहाई युवा ओआरएस पैकेट पर दिए गए निर्देश को भी सही तरह पढ़ने में असमर्थ थे।

जो युवा सरल गणितीय गणना करने में समर्थ थे वह भी उनका उपयोग दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में करने में अधिकांशतया सक्षम नहीं थे। इस दिशा में विशेष रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि मूल दक्षताओं का उपयोग युवा अपने जीवन उपयोगी कार्यों में सुगमता से कर पाएँ।

सर्वेक्षित युवाओं के 90% परिवारों में स्मार्टफोन उपलब्ध था। इनमें से लड़कों में इसकी उपलब्धि 46.7% और लड़कियों में केवल 19.8% के पास यह स्मार्टफोन उपलब्ध था। जहां तक कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रश्न है, सर्वेक्षित घरों में केवल 9% के पास ही यह उपलब्ध था। यह भी देखा गया कि जिनके घरों में लैपटॉप उपलब्ध था उनमें से 85% उसे काम लेने में समर्थ थे और जिनके पास नहीं था उनमें से 34% ही ऐसे थे जो उन्हें काम लेना जानते थे।

जिन युवाओं के पास स्मार्टफोन था उनमें से दो तिहाई उसे पढ़ाई के लिए एवं उससे संबंधित कुछ समस्याओं का पर वीडियो आदि देखने में समर्थ थे।

असर 2023 के आधार पर मुख्य निष्कर्ष यह निकाला गया है कि पढ़ने-लिखने और गणना की मूल दक्षताओं में जहां सुधार करने की आवश्यकता है वहीं पर इन अर्जित दक्षताओं का उपयोग दिन प्रति दिन के कामों में करने पर बल देने की और भी अधिक आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही भारत 'डेमोठाफिक डिविडेंड' का पात्र कहला सकता है। अन्यथा प्रगति की दौड़ में भारत के युवा धीरे-धीरे पिछड़ते ही जाएंगे अतः सरकारों को 14 से 18 वर्ष के युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

जब हमने हाल ही में अमृत महोत्सव वर्ष मनाया और स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब भी 14 से 18 वर्ष के 25% बच्चे दूसरी कक्षा की साधारण मातृभाषा की किताब भी नहीं पढ़ सकते और सरल गणना नहीं कर सकते। अनगिनत प्रयोग शिक्षाविदों ने शिक्षा में किए हैं। कई प्रकार की योजनाएं बनाई गईं और वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जारी की गई। असर का परिणाम देखकर तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट ही आई है। यह तब है जबकि राजकीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षक - प्रशिक्षण प्राप्त हैं एवं उन्हें अच्छा-खासा वेतन भी प्राप्त होता है। इसके बावजूद यदि ग्रामीण भारत के बच्चों की शैक्षिक स्तर की यह स्थिति है इसके पीछे कोई मूल कारण है जिसे संबोधित करना एवं उसका समाधान करना बहुत आवश्यक है। यदि इस गंभीर समस्या पर तत्काल उच्च प्राथमिकता से ध्यान नहीं दिया गया तो फिर भारत के 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' या जनसंख्या - लाभांश की बात करना बेमानी सिद्ध होगा।

दुर्भाग्य तो यह है कि विभिन्न दल सत्ता में आए किंतु किसी ने भी इस ओर कोई विशेष ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों से केवल नामांकन बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है और इसी कारण नामांकन की दृष्टि से आंकड़े लगभग शत प्रतिशत के पास कई साल पहले ही पहुंच चुके हैं। बोर्ड की परीक्षाओं का स्तर इतना कमजोर हो गया है कि सभी का उत्तीर्ण होना युवाओं को कोई उत्पादक कार्य करने के योग्य नहीं बना पाता है।

अधिक युवा जनसंख्या देश के लिए लाभकारी तब हो सकती है जब वह कुछ क्रियाशील हो एवं किसी प्रकार का काम करने में सक्षम हो। जो बालक 14 से 18 वर्ष की आयु तक भी साधारण गुणा भाग नहीं कर सकता हो वह किस प्रकार अपने आगे की पढ़ाई जारी रख पाएगा एवं किस प्रकार वह अपने जीविकोपार्जन योग्य कोई भी साधन अपना कर रोजगार प्राप्त कर सकेगा? बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण ही आज यह है कि जो युवा रोजगार के बाजार में प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में जुड़ रहे हैं, वे नियोक्ता के लिए अथवा स्वयं किसी प्रकार का व्यवसाय करके पर्याप्त आय जुटाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। असर के सर्वे में यह भी पता लगा है कि कई परिवारों के पास स्मार्टफोन हैं। कई बार तो इनके कारण मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे परिवेश में देश के भविष्य पर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह अवश्य लगता है। एक ओर जहां भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कगार पर है, वहीं करोड़ों की संख्या में युवा, यदि कुछ भी लिखने-पढ़ने और गणना करने में समर्थ नहीं होंगे तो वह आगे किसी प्रकार पढ़ाई करने में सफल हो पाएंगे?

दुर्भाग्य तो यह है कि विभिन्न दल सत्ता में आए किंतु किसी ने भी इस ओर कोई विशेष ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों से केवल नामांकन बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है और इसी कारण नामांकन की दृष्टि से आंकड़े लगभग शत प्रतिशत के पास कई साल पहले ही पहुंच चुके हैं। बोर्ड की परीक्षाओं का स्तर इतना कमजोर हो गया है कि सभी का उत्तीर्ण होना युवाओं को कोई उत्पादक कार्य करने के योग्य नहीं बना पाता है। कुछ दशक पूर्व, पांचवी या आठवीं पास व्यक्ति भी शुद्ध भाषा लिख पाता था और गणना की क्रियाएँ न केवल कर पता था अपितु कई बार तो वह मौखिक रूप से भी ऐसा करने में सक्षम होते थे। जैसे-जैसे हमने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के नाम पर जो भी प्रयोग किए वे वास्तव में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को कमजोर करने वाले ही सिद्ध हुए। अपना परिणाम बेहतर बताने के लिए हमने उत्तीर्ण होने के मापदंड को कम कर दिया। यह वैसा ही है जैसे ऊंची कूद वाले के लिए अर्हता अगर 2 मीटर रखी जाए तो बहुत थोड़े लोग सफल हो पाएंगे लेकिन यदि इसको घटकर एक मीटर कर दिया जाए तो लगभग सभी सफल हो जाएंगे। शिक्षा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम आजकल 90-95% रहते हैं, किंतु दसवीं पास विद्यार्थी यदि पुराने समय के पांचवी के बराबर भी योग्यता नहीं रखते हैं तो फिर इस प्रकार की तथाकथित पढ़ाई का लाभ क्या है? यदि हम चाहते हैं कि आज के बालक-बालिका, सक्षम नागरिक के रूप में उभरें, तो इसके लिए पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि नींव को, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत किया जाए। किसी भवन की कमजोर नींव पर कितनी ही भव्य इमारत बनाने का प्रयास किया जाए यह सम्भव ही नहीं है। या तो वह बनेगी नहीं और कभी दिखावे के लिए बना भी दी गई, तो उसके ढहने में अधिक समय नहीं लगेगा। राजस्थान के परिपेक्ष में देखें, एक आदेश निकाल कर बड़ी संख्या में विद्यालय तो खोल दिए जाते हैं, किंतु कई वर्षों तक उनमें महत्वपूर्ण शिक्षकों के पद रिक्त ही पड़े रहते हैं। कोई भी शिक्षा संभव कैसे है जब बालकों के लिए शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं? हाल ही में उदयपुर की यात्रा के समय कोटडा में पद स्थापित एक प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं और उनके अलावा केवल एक ही शिक्षक है। कल्पना कीजिए, उन बच्चों की शिक्षा की, जिस विद्यालय में 450 विद्यार्थी और 12 कक्षाएं हों।

सरकार का कोई अधिकारी या मंत्री, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, इस रिपोर्ट को किसी न किसी रूप में गलत बताने का प्रयास करेंगे। किंतु वास्तविकता में रिपोर्ट कितनी सही है, यह प्रत्येक वह व्यक्ति जानता है जिसने कभी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर स्कूलों का निष्पक्ष, निरपेक्ष रूप से आकलन करने का प्रयास किया हो। प्रारंभिक शिक्षा का किस प्रकार जीवन में उपयोग हो सकता है और जीवन में उपयोगी बहुत सारे काम जो बच्चों के लिए उपयोगी है वह किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से हो सकते हैं इस संबंध में विशेष प्रयास किए जाने के आवश्यक हैं। यह भाषा एवं गणना की मूलभूत दक्षता के बिना सम्भव नहीं है। वैसे तो यह सारी दक्षता बच्चों के पाठ्यक्रम के अनुसार पांचवी कक्षा तक ही आ जानी चाहिए, किंतु हकीकत तो 'असर' ने दिखाई है। शिक्षा की सही स्थिति जब कोई सामने लाने का प्रयास करता है तो उसे ही गलत सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। यह वैसा ही है जैसे खराब तो चेहरा हो, किंतु आईने को दोष देकर उसे साफ करने की कोशिश करते रहें। इस प्रवृत्ति को छोड़कर सच को स्वीकार करने का साहस तो जनप्रतिनिधियों और शिक्षा के उच्च अधिकारियों को जुटाना ही होगा।

मैंने स्वयं ने, इसी संपादकीय के विभिन्न स्तंभों में कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि कैसे प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि ईमानदारी से इस ओर ठोस प्रयास किए जायें। देश में बहुत बड़ी संख्या में 12वीं के विद्यालय, महाविद्यालय,तकनीकी महाविद्यालय आदि खोल दिए गए हैं। उन सब की शिक्षा ग्रहण करने में ग्रामीण क्षेत्र का वह बच्चा कैसे समर्थ हो पाएगा यदि उसकी नींव मजबूत नहीं है। स्वैच्छिक शैक्षिक संस्थाएं इस ओर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। राजस्थान में नई सरकार बनी है। उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए राजकीय विद्यालयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना सुनिश्चित करे और जो भी स्वैच्छिक संस्थाएं ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ इस क्षेत्र में कार्य करना चाहें, उन्हें प्रोत्साहित करे। नागरिक समुदाय और विभाग, दोनों के प्रयास मिलकर दुगुने हो जाएंगे और शिक्षा के स्तर में तेजी से सुधार सम्भव है।

बोर्ड को भी अपनी परीक्षा पद्धति पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जो बच्चा बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करके निकले, वह वास्तव में अपेक्षित दक्षताएं रखता हो ताकि वह भविष्य में उच्च शिक्षा ठाहण करना चाहे तो उसे कोई असुविधा न हो और साथ ही यदि वह अपने जीवकोपार्जन का कोई अन्य मार्ग अपनाना चाहे तो उसमें भी अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर सके।

आशा की जानी चाहिए कि 'असर' की इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाएगा एवं इस पर एक संवाद स्थापित करने के बाद उसके परिणाम स्वरुप आवश्यक कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा ताकि जब 'असर' की आगामी रिपोर्ट आए तो उसमें बेहतर संतोषजनक परिणाम हम प्राप्त कर सकें।

इस दिशा में अब और समय व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। अब और देर करने पर, देश की युवा पीढ़ी के साथ तो अन्याय होगा ही, देश के उज्जवल भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुम्बकम की प्रतिष्ठा है

डॉ. सतीश पूनियां

विश्व के इतिहास में 22 जनवरी 2024 की तारीख युगों-युगों तक याद रखी जाएगी। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि इस दिन सनातन हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बल्कि इसलिए भी कि भारत के धैर्य, बलिदान, त्याग और तपस्या की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि यह नए कालचक्र का उदगम है। भारत सहित दुनिया के 160 देशों में बसे हिंदुओं के लिए 22 जनवरी का दिन कई सदियों बाद आई जीवंत दीपावली है। दुनियाभर के हिंदुओं के मन के भावों को टीवी स्क्रीन पर उनके उत्साह से देखा और महसूस किया गया।

मैं स्वयं दो बार वर्ष 1990 और 1992 की अयोध्या कारसेवाओं में रहा हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस पल को अनुभव कर सकता हूं। मैं अपने भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा मान लीजिए कि ईश्वर की तपस्या करने वाले के सामने उसके ईश्वर साक्षात प्रकट हो गए हों। यह तो पक्का विश्वास था कि जिस स्थान पर हमने कारसेवा की थी, वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन यह पल हमारे जीवन में ही आ जाएगा, यह विश्वास नहीं था। अब जब पावन नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनातन की सभी परंपराओं के साधु-संतों-संन्यासियों की साक्षात उपस्थिति में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो निश्चित ही यह संपूर्ण भारतवर्ष के आत्मविश्वास, आत्मगौरव और श्रद्धा को कई गुना बढ़ाने वाला पल हमारे उस अधूरे विश्वास की पूर्णाहूति करने वाला अवसर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यह मंदिर गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठने वाले राष्ट्र की पहचान का मंदिर है और नव इतिहास का सृजन करता है। अयोध्या का भव्य राम मंदिर सिर्फ भारत के वैभवशाली गौरव का ही दर्शन नहीं करवाता, बल्कि भारत के भविष्य की भी तस्वीर प्रस्तुत करता है।

यह भारत के लोगों के उस अदम्य धैर्य और त्याग का भी प्रतीक है कि अपने ही देश में अपने ही आराध्य के मंदिर के लिए पांच सौ साल से संघर्ष करते करते कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन हमने अपनी श्रद्धा को मजबूती से पकड़े रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई देश अपनी ऐतिहासिक गांठों को उलझाने में उलझ गए, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जिसने अपनी ऐतिहासिक गांठ को न्यायपूर्ण तरीके से और सबके आपसी समन्वय से सुलझा लिया। राम भारत की आत्मा में बसते हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के सभी परिवारों को अयोध्या आने के लिए पीले अक्षतों का वितरण हुआ। जिस तरह से देशभर में पीले चावलों के लिए परिवार प्रतीक्षा कर रहे थे, वह हमारी आस्था और तपस्या पूरी होने के भाव को दर्शाता है। हर परिवार इस बात को लेकर उत्सुक था कि अब उनके राम टैंट में नहीं, बल्कि भव्य प्रासाद में विराजित होंगे और उन्हें उनके भव्य और दिव्य दर्शन होंगे। इसके लिए आने वाले दिनों में हरेक राज्य से विशेष रेलगाड़ियां भी चलाए जाने की योजना बन रही है।

अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की स्थापना भी है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस दृष्टि से रामलला का यह भव्य मंदिर राष्ट्र की चेतना का मंदिर है। भगवान राम सदियों से भारतवर्ष की चेतना में रमे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि यह भारत की दृष्टि और दर्शन का मंदिर है। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव हजारों हजार वर्षों के लिए होता है। राम की दृष्टि ही भारत की दृष्टि है। भारत राम की दृष्टि के साथ पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। पिछले नौ-दस वर्षों में जिस तरह से वैश्विक घटनाओं में भारत ने अपनी दृष्टि से दुनिया का नेतृत्व किया, उसका लोहा पूरे विश्व ने माना है। चाहे वह कोविड का दौर हो या फिर युक्रेन-रूस और हमास-इजराइली संघर्ष हो। भारत ने अपने आराध्यों के दर्शन से पूरी दुनिया को एक दृष्टि देने का काम किया है।

प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि आने वाला समय सिद्धी का है। निश्चित ही संकल्प के बाद सिद्धी का समय होता है। हमारा सदियों पुराना संकल्प पूरा हुआ है और अब समय आगे बढ़ने का है। कई सदियों के संघर्ष के बाद हम यहां पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय भारत का है। भारत की युवा पीढ़ी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के सामने हजारों वर्षों की प्रेरणा है। इस वक्त सकारात्मक परिस्थितियां हैं, इसलिए हमें बैठना नहीं है। भारत निश्चित ही समृद्धि के लक्ष्य पर पहुंचेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत की नई पीढ़ी नेतृत्व कर रही है, यह बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढा है। फिर चाहे हम जी-ट्वंटी की बात करें या फिर दुनियाभर के ताकतवर और छोटे देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध, हर मोर्चे पर भारत ने दुनियाभर के मुल्कों के साथ अपने संबंधों को मजबूत, आत्मीय और गहरा किया है। भारत ने उन बहुत छोटे छोटे देशों से भी अपने संबंध प्रगाढ़ बनाए हैं जहां पूर्ववर्ती सरकारों के प्रतिनिधि पहुंच ही नहीं पाए थे। प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वह सिर्फ भारत के लिए ही यह बात नहीं करते, वह पूरी दुनिया के लिए कहते हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी कहा है कि रामलला की प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिष्ठा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह क्षण हमें कर्तव्य बोध भी करवाता है। प्रधानमंत्री ने तीन सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए। गिलहरी, निषादराज और जटायु का। जिस तरह रामकाज के लिए गिलहरी और जटायु ने अपनी क्षमताओं के बावजूद अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा था। माता सीता की सुरक्षा लिए जटायु महाबली रावण से भिड़ गया था। उसे पता था कि वह रावण से जीत नहीं सकता, लेकिन इसके बाद भी उसने अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी हजारों कारसेवक अपना कर्तव्य निभाते हुए बलिदान हो गए। उन्हें भरोसा था कि कभी न कभी उनकी आहूति रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में समिधा बनेगी। अयोध्या में रामलला का भव्य और दिव्य प्रेरणादायी मंदिर विश्व के सामने भारत की अटूट आस्था, त्याग, बलिदान और पुरुषार्थ का साक्षात उदाहरण बनकर खड़ा है, जो पूरे विश्व को हजारों साल तक प्रेरणा देता रहेगा। जय श्री राम।

- डॉ. सतीश पूनियां,
(लेखक भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं)।

नई सरकार की प्राथमिकताएं

भागीरथ शर्मा

''अन्त्योदय''

-राजस्थान में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक नूतन प्रयोग

संक्षिप्त पृष्ठभूमि :- स्वतन्त्रता के पश्चात विकास योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन का सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस दिशा में इस शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में कई प्रयोग किए गये, जिनमें लघु कृषक विकास योजना एवं सीमान्त कृषक एवं खेतीहर श्रमिक विकास योजनाएं प्रमुख थी जो प्रयोग के तौर पर देश के कुछ चुने हुए जिलों में भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। राजस्थान के 5 जिले इस योजना में लिए गये थे, साथ ही सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास योजना में भी लघु कृषक विकास योजना के अनुरूप अनुदान सुविधाएं दी गई थी। इन सभी योजनाओं के मूल्यांकन से यह स्पष्ट हुआ कि इन कार्यक्रमों का लाभ मुख्य रूप से तुलनात्मक दृष्टि से खाते-पीते लघु कृषकों को ही मिल पाया था। सीमान्त कृषक या कृषि श्रमिक जो गरीबी की रेखा में सबसे नीचे के परिवार थे पूर्णतः वंचित रह गये। उपरोक्त निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए एवं राज्य में मोटे अनुमान के आधार पर वर्ष 1975 में लगभग 56 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे आंकलित होने के कारण देश में आयोजना से आर्थिक विकास के इतिहास में प्रथम बार राजस्थान सरकार ने वर्ष 77-78 में 2 अक्टूबर, 1977 को 'अन्त्योदय' के नाम से सर्वथा नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया। 'लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अन्त्योदय कार्यक्रम के प्रभारी एवं राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान के सदस्य व विश्व बैंक के सलाहकार रहे है।

कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से पूर्व एक संक्षिप्त 'अप्रोच पेपर' तैयार किया गया एवं राज्य विधान सभा के बजट सत्र में सितम्बर, 1977 में घोषणा कर 2 अक्टूबर, 1977 से अन्त्योदय के प्रथम दौर का कार्यक्रम लागू कर दिया गया। उक्त पेपर के आधार पर राज्य के सभी लगभग 33000 गावों मे से प्रत्येक गांव से 5 निर्धनतम परिवारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके पश्चात, जून,1978 में इस नूतन योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके आधार पर तत्कालीन कृषि पुनर्वित निगम से 187 करोड की ऋण राशि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी प्राप्त की गई एवं इस परियोजना प्रतिवेदन की प्रति तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भैरुसिंहजी शैखावत द्वारा लोक नायक जयप्रकाश नारायणजी को पटना सम्मेलन में भी प्रस्तुत की गई।

कार्यक्रम की रूपरेखा :- अन्त्योदय का शाब्दिक अर्थ है - 'अन्तिम पंक्ति के आखरी व्यक्ति का आर्थिक उत्थान' -सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति का चयन कर उसे सबसे पहले लाभान्वित करना ही इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था। कार्यक्रम के लाभ की प्रक्रिया नीचे से प्रारम्भ होकर वार्षिक चक्रो से चक्र दर चक्र उपर की ओर बढना ही प्रमुख लक्ष्य रखा गया था।

चयन का आधार केवल 'आर्थिक निर्धनता' ही रखा गया था चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म समुदाय का हो। कार्यक्रम क्षेत्रीय असमानता से सर्वथा मुक्त रखा गया था। राज्य के सभी 33000 ग्रामों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिवर्ष 3,5,7 व 10 परिवारों का चयन कर उसी वर्ष के वार्षिक चक्र में ही उन्हें लाभान्वित कर दिया जाने की क्रियान्वयन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इस अभियान के दौरान ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं राजस्व अधिकारियों ने गांव-गांव में शिवर आयोजित कर ग्राम सभाओं में निर्धनतम परिवारों का चयन किया एवं उनको आर्थिक संसाधन देने के लिए ग्राम सभा द्वारा चयनित परिवारों से प्राप्त 'संसाधन विकल्पों' का अनुमोदन कराकर मौके पर ही सहायता व ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करने की प्रक्रिया अपनाई गई।

निर्धनतम परिवारों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने में सबसे बडी बाधा अनुदान के साथ ऋण उपलब्धता की थी। बैंक, जमानत व जटिल प्रक्रिया पूरी किये बिना ऋण नही देते थे। अधिकांश प्रयोजनों के साथ जमीन रहन रखना आवश्यक था। इस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को राज्य की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तृत कर डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक के साथ जून, 1978 में ही परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उच्च स्तरीय बैठक रिजर्व बैंक मुख्यालय पर करवाई गई एवं रिजर्व बैंक की ऋण नीति में प्रथम बार भारी संख्या में आमूलचूल परिवर्तन करवाए गये। डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक को राज्य के 7-8 जिलों का सघन दौरा करवाकर आश्वस्त भी किया गया एवं इसी आधार पर 5 वर्ष की प्रोजेक्ट अवधि में लगभग 6 लाख परिवारों को लाभान्वित करने हेतु 187 करोड रूपये की ऋण राशि उपलब्ध कराने का निर्णय कराया गया।

कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं जिला प्रशासन को उत्तरदायी बनाया गया एवं प्रति पखवाडें प्रगति की सूचना प्राप्त कर प्रगति की समीक्षा की भी नई प्रणाली लागू की गई जिसमें जिलों के नाम उनकी प्रगति की प्रतिशत के आधार पर क्रमवार लिखे जाते थे एवं बीच में 'राज्य औसत' की रेखा अंकित की जाती थी।

प्रशासनिक व्यवस्था :- कायक्रम के क्रियान्वय व्यवस्था में नीतिगत निर्णयों हेतु राज्य में उच्चतम स्तर पर मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में नीति निर्धारण समिति का गठन किया गया। जिसके सदस्यों में सम्बन्धित मंत्रीगण को रखा गया। निगरानी का उत्तरदायित्व अधिकारी स्तर की कमेटी को सौपा गया जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव थे। राज्य सरकार के स्तर पर, कार्यक्रम की क्रियान्विति का भार पूर्णाधिकर प्राप्त 'अन्त्योदय' आयुक्त को सौपा गया जिनकी सहायता हेतु परियोजना निदेशक (क्रेडिट) को अन्त्योदय कार्यक्रम का प्रभारी अधिकारी बनाया गया।

प्रगति का सिंहावलोकन :- वर्ष 1977-78 (2 अक्टूबर, 1977) में प्रारम्भ किये गये अन्त्योदय कार्यक्रम के 2 वार्षिक चक्र पूर्ण किये गये। जिसके आधार पर प्रथम चक्र में 1,39,986 परिवारो को लाभान्वित किया गया। प्रथम चक्र में कतिपय निर्धतनम परिवारों ने संकोच एवं अज्ञानतावश सहायता लेने से मना भी कर दिया था जो अन्य परिवारों की उन्नति से प्रभावित होकर द्वितीय चक्र में लाभ लेने हेतु स्वतः ही आगे आ गये। द्वितीय चक्र 78-79 में भी चयनित लगभग 1,12,000 परिवारों को चयनित कर लाभान्वित किया गया।

मूल्यांकन :- राज्य में लागू की गई इस अनूठी योजना से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश, कार्नाटक आदि कई राज्यों से एवं श्रीलंका, मलेशिया आदि अन्य देशों के प्रतिनिधिगण एवं विश्व बैंक के उस समय के अध्यक्ष मेकना मारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष भोला पासवान आदि ने राज्य में आकर इस योजना को देखा एवं सराहना की। कुछ राज्यों ने इस योजना को अपने यहाँ लागू भी कर दिया। हिमाचल में यह योजना सम्भवतः पूर्वानुसार कुछ वर्ष पूर्व तक चालू थी।

योजना आयोग के मूल्यांकन सम्भाग द्वारा अन्त्योदय के दोनों ही चक्रों (1977-78 व 1978-79) का सघन मूल्यांकन करवाया गया। केन्द्र में अन्य पार्टी का शासन होने के कारण यह मूल्यांकन और भी गहराई से किया गया। क्योंकि इस योजना की भारी सफलता एवं प्रशंसा से वे आश्वस्त नही थे। योजना आयोग के अतिरिक्त सचिव श्री बागला ने स्वयं परीक्षण मूल्यांकन गांवों में जाकर किये एवं उनकी रिपोर्ट में इस योजना की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई। परिवारों की आय में वृद्धि, कारगर क्रियान्विति व्यवस्था, पश्चातवर्ती देखरेख, कारगर चयन प्रक्रिया, ग्राम सभा की भागीदारी से सभी ग्रामीणों को इस योजना का ज्ञान, चयनित परिवार एवं उन्हें दिये गये लाभ की बच्चे-बच्चे को जानकारी होना आदि इस योजना की विशेषताए बताई गई एवं इस योजना की उपलब्धियों को प्रशंसनीय बताया।

दुर्भाग्यवश राज्य में 1979-80 में सरकार परिवर्तन के साथ इस अनूठे कार्यक्रम को, जो गरीबी उन्मूलन के लिए लागू किये गये अब तक के सभी कार्यक्रमों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं कारगर कार्यक्रम था, एवं केवल दो चक्र ही पूरे हुए थे, कांग्रेस की नई सरकार द्वारा अचानक बन्द कर दिया गया। जिसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई एवं इसका यह लाभ अवश्य हुआ कि तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर इसके विकल्प के रूप में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में लागू कर दिया। पर उक्त कार्यक्रम जिसे अब स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार कार्यक्रम नाम दिया गया है, अभी तक भी लगभग 2 दशक से अधिक अवधि में भी वे सफलताएं अर्जित नही कर पाया है। जो 2 वर्ष की अल्पावधि में अन्त्योदय कार्यक्रम में की गई थी। अन्त्योदय की कारगर चयन व क्रियान्विति प्रक्रिया, पश्चातवर्ती देखरेख व्यवस्था तथा सभी विभागों के अन्य कार्यक्रमों एवं विपणन व्यवस्था से सुदृढ कडीबन्धन आदि विशेषताओं का अभाव, आज भी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सबसे बडी कमजोरी है। तत्कलीन भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान में ही चलाये गये अन्तोदय कार्यक्रम ने जो जन-जन में विश्वास अर्जित कर अपनी साख पैदा की थी वह अन्य किसी भी कार्यक्रम में नही हो पाया है। ऐसे लोकप्रिय कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन का प्रमुख कार्यक्रम बनाकर पुन; नयी भाजपा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में पुनः लागू किया जाना सामयिक होगा।

- भागीरथ शर्मा,
आई. ए. एस. (से.नि)।

राशिफल मंगलवार 23 जनवरी, 2024

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, आर्द्रा नक्षत्र बुधवार प्रातः 6:26 तक, ऐन्द्रयन योग प्रातः 8:04 तक, कौलव करण प्रातः 8:16 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मेष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से बुधवार प्रातः 6:26 तक है। रवियोग बुधवार प्रातः 6:26 तक बना रहेगा। आज भौम प्रदोष व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:54 से 11:19 तक, लाभ-अमृत 11:19 से 1:58 तक, शुभ 3:18 से 4:37 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:57

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मानसिक तनाव और मन में असंतोष बना रहेगा। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचिता सोच-विचार हो सकता है।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना पड़ सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

धनु
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा।

मीन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।